तापमान

भोपाल	27.0°	10.2°
इंदौर	27.6°	13.2°
जबलपुर	26.8°	9.0°
ग्वालियर	28.4°	10.9°

दैनिक

नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

वर्ष- 78
(भोपाल : वर्ष 40 अंक 01 ,पृष्ठ 12)
शुक्रवार 29 नवम्बर 2024
राजधानी संस्करण
कीमतः 3:00 रुपये

राजधानी... मनी लॉन्ड्रिंग- आतंकवाद की फंडिंग रोकने में...

खेल... बजरंग पूनिया ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप...

व्यापार... हुआई ने लांच किए नई मेट 70 सीरीज के...

देश-विदेश... पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तेवर...

www.naiduniaonline.com

अदाणी और संभल मुद्दे पर लोकसभा में गतिरोध बरकरार, लोकसभा में हंगामा जारी, कार्यवाही स्थगित

वक्फ समिति का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने अदाणी समूह से जुड़े मामले तथा उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अदाणी मुद्दे और संभल हिंसा को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर कांग्रेस और सपा के सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही, सदन ने वक्फ (संशोधन) विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2025 के आखिरी दिन तक बढ़ाने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सदन में हंगामे को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी ने मिलकर फैसला किया था कि कौन सा विधेयक आएगा और कब आएगा जो बाकी मुद्दे हैं उन पर चर्चा का अलग अलग नियम बना हुआ है।

रीजीजू ने कहा कि यहां कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने बिना किसी नियम के और तय नियमों को तोड़ते हुए हंगामा करने की कोशिश की है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह ठीक नहीं हैं। उनका कहना था कि कई सदस्य अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाना चाहते हैं। रीजीजू ने कहा कि वक्फ विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग विपक्षी सदस्यों ने की थी और अब जब इससे जुड़ा प्रस्ताव आया तो कांग्रेस तथा उसके सहयोगी नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजकर पांच मिनट पर पीठासीन सभापति ने सभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, बृहस्पतिवार सुबह सदन की बैठक शुरू होने के करीब सात मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही केरल की वायनाड सीट से सदन की सदस्य निर्वाचित हुईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और महाराष्ट्र के नांदेड़ से सदस्य निर्वाचित हुए इसी पार्टी के रवींद्र चव्हाण ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली।

इसके बाद जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस सदस्य अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठा रहे थे, वहीं सपा सांसद संभल हिंसा का मुद्दा उठाते देखे गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक पूरक प्रश्न का उत्तर भी दिया। बिरला ने इस दौरान नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा। आप नियोजित तरीके से सदन को अवरुद्ध करना चाहते हैं। जनता ने आपको अनेक आकांक्षाओं के साथ यहां भेजा है, आपको उनकी चिंताएं और क्षेत्र की समस्याएं उठानी चाहिए। बिरला ने कहा कि जिन मुद्दों का देश से कोई संबंध नहीं है, आप उन्हें यहां उठा रहे हैं, चर्चा के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। उन्होंने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील करते हुए कहा कि गतिरोध का यह तरीका ठीक नहीं है। संविधान सभा में भी चर्चा हुई थी, सहमति-असहमति रही थी, लेकिन सदस्यों का आचरण मर्यादित रहा था। आपका यह व्यवहार मर्यादित नहीं है। बिरला के बार-बार अपील करने के बाद भी आसन के समीप खड़े कांग्रेस और सपा सांसदों की नारेबाजी जारी रही।

राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी

अडानी समूह में कथित अनियमिताओं की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर राज्यसभा में गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले स्थगन के बाद जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अपनी सीटों से आगे आकर खड़े हो गए और जोर-जोर से बोलने लगे। इस पर श्री धनखड़ ने कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लेने के निर्देश दिए। श्री धनखड़ ने सदस्यों से शांत होने की अपील करते हुए कहा कि यह वरिष्ठों का सदन है और 140 करोड लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना इस सदन के सदस्यों का कर्तव्य है। सदस्यों को यह कर्तव्य अवश्य ही पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद सकारात्मक संवाद का स्थान है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जर्मनी के म्यूनिख पहुंचने पर जर्मनी में मौजूद भारतीय कॉउंसलेट ने पुष्प-गुच्छ भेंटकर स्वागत किया।

भारतीय टेक्नोलॉजी और जर्मन एक्सपर्ट्स के...

समन्वय से होगा औद्योगिक विकास

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को जर्मनी दौरे पर बवेरिया राज्य के चांसलरी प्रमुख और संघीय एवं यूरोपीय मामलों के साथ मीडिया विभाग के मंत्री डॉ. फ्लोरियन हैरमेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्य स्तर पर सहयोग के विभिन्न अवसरों पर चर्चा की गई।

मध्यप्रदेश और बवेरिया के बीच सहयोग और साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मुलाकात

चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं डॉ. हैरमेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जर्मनी के बीच मजबूत होते रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य स्तर पर भी साझेदारी बढ़ाने पर रजामंदी दिखाई। दोनों नेताओं ने तकनीकी नवाचार, सुपरकंप्यूटिंग, ऑटोमोटिव सेक्टर, एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग के पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। डॉ. यादव जर्मन प्रतिनिधिमंडल के टाइम मैनेजमेंट से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जो समय को जीतता है, वह दुनिया को जीत सकता है। उन्होंने जर्मनी की आर्थिक सुदृढ़ता और परिवर्तन को प्रेरणादायक बताते हुए इसे राष्ट्रीय विकास और रणनीतिक प्रगति का एक आदर्श मॉडल निरूपित किया। दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को मध्यप्रदेश और बवेरिया के बीच दीर्घकालिक और आपसी लाभकारी संबंधों का शुभारंभ बताया। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश और बवेरिया के बीच जलवायु नीति से जुड़े संकटों का समाधान, तकनीकी नवाचारों, उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने की दिशा में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के मंडीदीप और पीथमपुर में पहले से मौजूद जर्मन निवेशों के सुगम समन्वय के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में एक विशेष राज्य सरकारी संपर्क कार्यालय स्थापित करने की योजना पर भी चर्चा (शेष पेज 2 पर)

खास-खबरें

डीजी-आईजी सम्मेलन को लेकर आतंकी पन्नू ने दी धमकी

भुवनेश्वर (एजेंसी)। भुवनेश्वर में ओडिशा डीजीपी सम्मेलन से एक दिन पहले, खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने गुरुवार को एक संदेश जारी कर अखिल भारतीय बैठक को बाधित करने की धमकी दी, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे। सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन के प्रमुख पन्नू ने एक वीडियो संदेश में अपने समर्थकों से डीजी-आईजी सम्मेलन को बाधित करने के लिए भुवनेश्वर के मंदिरों-होटलों में भेष बदलने और छिपने का आग्रह किया।

लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी को रवांडा से लाया गया भारत

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बेंगलुरू जेल आतंकी साजिश मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े भगोड़े सलमान रहमान खान को रवांडा से भारत लाने में सफलता पाई। एनआईए ने यह ऑपरेशन रवांडा जांच ब्यूरो (आरआईबी), इंटरपोल और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) के सहयोग से अंजाम दिया। सलमान को 27 नवंबर 2024 को रवांडा की राजधानी किगाली में गिरफ्तार किया गया था। इंटरपोल के रेड नोटिस और बेंगलुरु की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया।

बदलते परिदृश्य में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे सेनाः मुर्मु

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि तेजी से बदलती भू-राजनीतिक स्थिति में सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। श्रीमती मुर्मु ने गुरूवार को तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारियों और शिक्षकों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि देश विकास के पथ पर आगे बढ रहा है और दुनिया रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे विकास को स्वीकार कर रही है। भारत भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों को तैयार रखने के लिए स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार और बड़ा रक्षा निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है बल्कि साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी नई राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी (शेष पेज 2 पर)

उच्चतम न्यायालय ने यासीन मलिक से किया जवाब-तलब

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या और 1989 में मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले से जुड़े गवाहों की जिरह के लिए संबंधित मुकदमा जम्मू से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर गुरुवार को आरोपी यासीन मलिक से जबाव तलब किया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। पीठ ने मामले के आरोपी और तिहाड़ जेल में बंद मलिक को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवताओं के अपमान और क्षति की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और सरकार से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आव्हान किया। संसद में विदेश मंत्रालय का बयान बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों द्वारा इस्कॉन और अन्य मंदिरों को निशाना बनाए जाने को लेकर अशांति की ताजा लहर के बीच आया है।

राज्यसभा में एक जवाब में, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने ऐसी घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जिसमें ढाका के तांतीबाजार में एक पूजा मंडप पर हमला और दुर्गा पूजा 2024 के दौरान सतखिरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी शामिल है। पिछले महीने ढाका के तांतीबाजार इलाके में एक दुर्गा पूजा मंडप पर देसी बम फेंका गया था। हालाँकि, कोई चोट नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में अपनी यात्रा के दौरान उपहार (शेष पेज 2 पर)

जनता के मुद्दे संसद में उठाना मेरी प्राथमिकता रहेगी : प्रियंका

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उनके लिए संविधान सबसे ऊपर है और संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

श्रीमती वाड्रा ने लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ वह संविधान को मजबूती प्रदान करने की लड़ाई लड़ती रहेंगी और जनता के मुद्दे संसद में उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जनता के जरूरी मुद्दों को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि श्रीमती वाड्रा के संसद में आने से पार्टी को नयी ऊर्जा (शेष पेज 2 पर)

हेमंत सोरेन ने चौथी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

रांची (एजेंसी)। झारखंड में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शाम चार बजे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 49 वर्षीय नेता का मुख्यमंत्री के रूप में यह चौथा कार्यकाल होगा। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा कई अन्य नेता मौजूद थे।

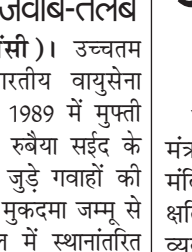

हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ को करना चाहिए हस्तक्षेप

नई दिल्ली (एजेंसी)। हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की बांग्लादेश में गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त राष्ट्र संघ से हस्तक्षेप की मांग की है। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वहां की सरकार चरमपंथियों के दबाव के आगे झुक गई है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों में कोई अंतर नहीं है। भारत सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। मैंने कल भी कहा था और आगे भी कहना जारी रखूंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि छोटे-छोटे जज इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। इसको लेकर सियासत गरमा गई है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाना रामगोपाल यादव की पार्टी के डीएनए में है, भले ही उनका नाम रामगोपाल है, लेकिन वह हिंदुओं पर गोली चलाने और उनके अधिकारों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने यही किया था। उन्होंने वोटों के लिए मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की थी। जब अत्याचार होंगे तो हिंदू कहां जाएंगे?

स्कूलों को छोड़कर दिल्ली में अभी लागू रहेंगी पाबंदियांः सुको

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में उच्च प्रदूषण स्तर पर दिल्ली के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रेप 4 उपायों का कार्यान्वयन एक घोर विफलता था। अदालत ने फैसला सुनाया कि स्कूलों पर प्रतिबंध को छोड़कर सभी प्रदूषण विरोधी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। अदालत ने प्रदूषण विरोधी संस्था सीएक्यूएम को इस बीच एक बैठक आयोजित करने और प्रतिबंधों को जीआरएपी 4 से घटाकर जीआरएपी 3 या जीआरएपी 2 तक कम करने पर सुझाव देने पर विचार करने का आदेश दिया। अदालत ने निकाय से जरूरत पड़ने पर ग्रेप 4 और ग्रेप 3 उपायों वाले एक हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर विचार करने को कहा।

स्पेशल खबर *मोदी के तीसरे कार्यकाल में 60 हजार से अधिक...*

सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र जारीः मांडविया

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस के बेकाबू बेरोजगारी के आरोप ----को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अभी तक 60 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं।

श्री मांडविया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रोजगार के नये अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार के गठन के बाद से नवंबर के पहले सप्ताह तक 60 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।

युवाओं को ये नौकरियां केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में उपलब्ध करायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों 4300 युवाओं पर भर्ती किया गया है। इसके अलावा 5000 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने विभिन्न आंकड़ों और अध्ययनों के हवाले से कहा कि सरकार बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने एक अध्ययन के हवाले से कहा कि बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्र में एक करोड़ रुपए का निवेश होने से लगभग छह लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के अंतर्गत 3.39 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। सरकार के भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं को देखते हुए एक करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप देने का प्रावधान किया।